

चौधरी चरण सिंह

एक संक्षिप्त जीवन सार

द्वारा - हर्ष सिंह लोहित

प्रोफेसर पॉल आर. ब्रास द्वारा लिखित जीवन वृत्तांत पर आधारित
http://www.paulbrass.com/files/Charan_singh_dn.doc

भारत के पांचवे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह (१९०२-१९८७) का जन्म २३ दिसम्बर १९०२ को संयुक्त प्रांत के मेरठ जिले के नूरपुर ग्राम में हुआ था। वे बटाई पर खेती करने वाले एक परिश्रमी काश्तकार मीर सिंह एवं नेत्री कौर की पॉच संतानों में सबसे बड़े थे। यह परिवार कृषि आधारित स्थायी जीवन यापन की आकांक्षा लिए, उपयुक्त भूमि की तलाश में मेरठ जिले में ही एक गांव से दूसरे गांव जाता रहा और अन्ततः १९२२ में भदौला ग्राम में बस गया।

चरण सिंह की स्कूली शिक्षा जानी खुर्द ग्राम में हुई। वे एक सक्षम एवं मेधावी छात्र थे। आगे की पढ़ाई के लिए वह मेरठ शहर आ गये, जहां से उन्होंने १९१९ में गवर्नर्मेंट हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा पास की। तदुपरान्त उन्होंने आगरा शहर के आगरा कालेज में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने १९२३ में बी० एस० सी०, १९२५ में इतिहास में एम. ए. और १९२६ में एल. एल.बी. की परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं। उन्होंने गाजियाबाद में दीवानी (सिविल लॉ) में वकालत करनी आरम्भ की, परन्तु शीघ्र ही वे (१९२९ में) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गये और अपनी अल्पकालिक वकालत को त्यागकर उन्होंने पूर्णकालिक राजनीतिक जीवन को अपना लिया।

चरण सिंह को एक खेतिहर कृषक परिवार में लालन-पालन होने पर जीवनभर गर्व रहा। अथव परिश्रम, स्वतंत्रता एवं दृढ़ ईमानदारी जीवन मूल्यों से वे सदैव आप्लावित रहे। उनके जीवन को आलोकित करने वाले तीन प्रभाव प्रमुख हैं, जिनमें प्रथम और सर्वाधिक प्रभाव गाम्य जीवन की कृषक शैली का रहा, जिसने उनके जीवन में नैतिक सिद्धांतों को पुष्ट में प्रमुख भूमिका निभाई और उनके बौद्धिक एवं राजनीतिक विचारों को स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने हमेशा ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा पोषित जमींदारी-व्यवस्था की सख्त आलोचना की, जिसके चलते छोटे काश्तकार एक ओर तो बड़े जमींदारों की दया पर निर्भर थे तो दूसरी ओर भारी लगान वसूली से आतंकित भी और इसी कारण उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य (जो आजादी से पहले संयुक्त प्रांत कहलाता था) में जमींदारी उन्मूलन में उनकी भूमिका प्रमुख रही।

उनके जीवन पर दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव स्वामी दयानन्द के आर्यसमाज का पड़ा, जिससे उनका परिचय १९१८ के आसपास हुआ और तीसरा प्रभाव महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाये जा रहे स्वतंत्रता आन्दोलन का रहा। उन्होंने अपने लोक जीवन और निजी जीवन को सदैव समरस और परदर्शी बनाये रखा और उसे प्राचीन नैतिक शिक्षाओं पर आधारित आर्यसमाज के जाति विहीन आदर्श हिन्दू समाज की परिकल्पना

से संवारा, जिसमें थोथे धार्मिक विधि-विधानों और ऊंची जातियों के प्रभुत्व का कोई स्थान न था। इसी दौरान उन्होंने गांधी जी के 'सादा जीवन – उच्च विचार' के ग्रामीण भाव को भी आत्मसात किया, जिसमें आजादी के बाद भारत के सामाजिक एवं राजनैतिक परिदृश्य के केन्द्र में आत्मनिर्भर गांव का प्रतिष्ठापन सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास के एक ऐसे मॉडल को सामने रखा, जो अंग्रेजी शासन और उसकी नीतियों से— जो ग्रामीण भारत की जनता की लोकतांत्रिक भावना एवं उनकी उद्यमशीलता को दबाने एवं गुलाम बनाने का कार्य करती थी— सर्वथा अलग और मुक्त था। वे भारत के स्वतंत्र शहरी क्षेत्रों के 'भूरे साहबों, ऊंची जातियों, शिक्षित नौकरशाही, राजनीतिज्ञों एवं पूँजीपतियों के घोर आलोचक रहे, क्योंकि वे इन्हें ग्रामीण बहुल जनता का शोषण करने में पूर्व श्वेत शासकों से भी आगे मानते थे।

राष्ट्रीय आन्दोलनों एवं कांग्रेस के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियानों में भाग लेने के दौरान १९३०, १९४० और १९४२ में उन्हें जेल जाना पड़ा। उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री देवी (१९०४–२००२, जो वर्तमान हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले से थीं) ने इन आन्दोलनों के दौरान उन्हें भरपूर सहयोग दिया और पाँच पुत्रियों एवं एक पुत्र के पालन-पोषण की महत्ती जिम्मेदारी संभाली। बाद के वर्षों में वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए दो बार, यथा— १९६९ व १९७४ में तथा १९८० में लोकसभा के लिए चुनी गई।

अपने सम्पूर्ण राजनैतिक जीवन में चरण सिंह ने भारतीय राजनीति के सभी आयामों को प्रभावित किया, फिर चाहे वह पश्चिमी संयुक्त प्रांत में उनका अपना जिला मेरठ रहा हो अथवा पूरा राज्य; और फिर तो वे राष्ट्रीय राजनीति के अंग बन गये। संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए वे पहली बार १९३७ में चुने गये। वहां उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के जीवन—यापन से सम्बंधित मुद्दों को जोर—शोर से उठाया। शीघ्र ही वे प्रांत के मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत के निकट आ गये, जिन्होंने दूसरी कांग्रेस सरकार (१९४६ से १९५०) में संसदीय सचिव (कनिष्ठ मंत्री) बना दिया। यद्यपि मंत्रिमंडल में उनका स्तर कनिष्ठ था, फिर भी पंत जी ने उन्हें वरीयता देते हुए जर्मींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार बिल का प्रमुख वास्तुकार एवं प्रतिरक्षक नियुक्त किया। अन्ततः १९५२ में यह बिल कानून में बदल गया। लाखों—लाख किसानों के सशक्तीकरण और शोषक जर्मींदार वर्ग को बड़ी शांति से शक्तिविहीन कर देना— अपनी इन दो उपलब्धियों को चरण सिंह अपने राजनैतिक जीवन की चरम उपलब्धि मानते थे।

१९५९-१९६० के उन्नीस महीनों को छोड़ दें तो १९५१ से लेकर १९६७ तक उत्तर प्रदेश में बनने वाले प्रत्येक कांग्रेसी मंत्रिमंडल में वे काबीना स्तर के मंत्री रहे। इस दौरान राज्य सम्बंधी कानून—व्यवस्था, राजस्व, भूमि, कृषि, वन और शांति व्यवस्था से जुड़े पेचीदा मुद्दों का उन्होंने गहन अध्ययन किया, जिसके बल पर वे उत्तर प्रदेश में तथा बाद में देश के समक्ष आने वाली बड़ी समस्याओं का समाधान अपूर्व ढंग से कर देते थे।

सरकार से सम्बंधित प्रशासन में अपने दो दशकों के सक्रिय अनुभव के चलते और हठ की हद तक दृढ़ी होने के बावजूद उनकी गणना देर तक कार्यालय में पूरे समर्पणभाव से कार्य करने वाले, सुस्ती के खिलाफ और भ्रष्टाचार से कभी समझौता न करने वाले तथा प्रशासन में एक निष्णात जन सेवक के रूप में होती थी।

शक्तिशाली और प्रभावी होने की प्रक्रिया में चरण सिंह के मध्यमवर्गीय कृषक समाज के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में जाना गया। हालांकि वह स्वयं आर्य समाजी थे और हिन्दू सुधार आन्दोलन से जुड़े हुए थे, जो सामाजिक एवं लोकजीवन में जातिगत पहचान की सभी संभावनाओं को नकारता था, फिर भी उन्हें अपनी जाति का भरपूर समर्थन हमेशा प्राप्त होता रहा और उनकी पहचान भी ऊँची धनी जातियों एवं निम्नतम जातियों के मध्य स्थित और निचले सामाजिक स्तर वाली तथाकथित पिछड़ी खेतिहर जाति से ही कायम रही।

वे एक महत्वपूर्ण, बौद्धिक और प्रमाणिक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों के साथ-साथ काफी संख्या में राजनैतिक परचे एवं राजनैतिक दलों के लिए घोषणा-पत्र लिखे, जिनसे भारत के सम्बद्ध विकास की वैकल्पिक योजनाओं व तौर-तरीकों पर उनके सुर्खेत विचारों की जानकारी मिलती है। वे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा पूंजीगत औद्योगिकीकरण पर बल दिये जाने के विरुद्ध थे और कृषि, गांवों और श्रम आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुरजोर समर्थन करते थे। उनके समयपूर्व विचार वैश्विक चिंतकों (जैसे माइकल लिपटन) से दशकों आगे थे, जिन्हें उन्होंने सोदाहरण और तर्कसंगत ढंग से सामने रखा। उनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण प्रकाशनों में एबोलिशन ऑफ जर्मीदारी : टू अल्टरनेटिव (१९४७), एग्रेसियन रिवॉल्यूशन इन उत्तर प्रदेश (१९५२), ज्वाइंट फार्मिंग एक्सरेड : दि प्रोब्लम एण्ड इट्स सोल्यूशन (१९५९), इंडियाज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन (१९६४), इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी : दि गांधियन ब्लूप्रिंट (१९८१) प्रमुख हैं।

१९६७ में कांग्रेस पार्टी के घटकों में अन्दरखाने चल रहे षड्यंत्रों से असंतुष्ट होकर चरण सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और उत्तर प्रदेश में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार स्थापित की। उन्होंने तब एक नये राजनैतिक दल भारतीय क्रांति दल का गठन किया, जिसका जनाधार मुख्यतया उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्ग के कृषक समाज से और बाद में उत्तरी भारत से रहा। वे उत्तर प्रदेश में १९६७-६८ के दौरान व १९७० में पुनः मुख्यमंत्री बने। भारत की मिली-जुली संविद राजनीति के बहु प्रथम पथ-प्रदर्शक थे। १९७४ में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तब चरण सिंह ने अपनी पार्टी का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में विलय कर एक नई पार्टी 'भारतीय लोकदल' का गठन किया और कांग्रेस की सत्ता के लिए केन्द्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर चुनौती पेश कर दी। दुबारा कांग्रेस में लौटने एवं मंत्रिमंडल में आने के सन्दर्भ में इंदिरा गांधी और उनके बीच सीधी एवं मध्यस्थों के जरिये अनेक बार वार्ता हुई, जो अंततः टूट गयी। दो भिन्न परन्तु सुदृढ़ विचारधारा वाले व्यक्तित्वों और उनकी सर्वथा अलग पृष्ठभूमि के चलते ऐसा होना स्वाभाविक ही था।

१९७५ से १९७७ के मध्य, इंदिरा गांधी के निरंकुश 'आपातकाल' में उन्हें अनेकों प्रतिपक्षी अग्रणी राजनेताओं के साथ जेल भेज दिया गया, जहां वे लगभग एक साल तक रहे। रिहाई के बाद चरण सिंह की भारतीय लोकदल पार्टी की उत्तरी भारत के कृषक वर्ग में भारी पैठ होने के कारण उसका भारी समर्थन, भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ और कांग्रेस (ओ) के विलय के बाद बनी जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, जिसके कारण १९७७ के आम चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई और इंदिरा गांधी के अस्थाई उतार के साथ-साथ स्वातंत्र्योत्तर भारत में प्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ।

चरण सिंह १९७७ से १९७९ के बीच नई दिल्ली में जनता सरकार में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत उपप्रधानमंत्री होने के साथ ही भारत के गृहमंत्री भी रहे और जुलाई १९७९ में जनता पार्टी की टूट के चलते थोड़े समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। १९८० के आम चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस जीत कर सत्ता में वापस आ गये। यद्यपि चरण सिंह उक्त चुनाव में लोकसभा के लिए चुने गये थे (उनकी पार्टी ने लोकसभा में ४१ सीटें जीती थीं और लोकसभा में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी) और १९८४ के आम चुनाव में भी वे विजयी रहे तथा लोकदल पार्टी का लगातार नेतृत्व किया, परन्तु वे दोबारा सरकार के अंग नहीं बने।

इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने उत्तर भारत की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है और मध्य वर्ग के कृषक समाज में उनकी गहरी पैठ का भरपूर लाभ उनके राजनैतिक उत्तराधिकारियों ने उठाया है। मध्यवर्ती जातियों और निचले दर्जे के काश्तकारों को साथ-साथ लाने के मूल में उनकी सफल भूमिका थी और इस विरासत का लाभ भी उनके राजनैतिक उत्तराधिकारियों ने बखूबी उठाया। एक सक्रिय राजनेता के रूप में चरण सिंह की अक्षुण्ण पहचान, सदैव, किसी भी चुनौती से परे, एक सत्यनिष्ठा-एवं ईमानदार राजनेता और अनथक परिश्रमी तथा प्रभावी प्रशासक की रही है। नवम्बर १९८५ में उन्हें तीक्ष्ण हृदयघात हुआ और नई दिल्ली में २९ मई १९८७ को उनका देहांत हो गया। इसके साथ ही एक निर्भीक, स्पष्टवादी और ग्रामीण भारत के कल्याणकारी मुद्दों से जुड़े एवं उनके प्रति पूर्णतः समर्पित एक स्वप्नदृष्टा के युग का भी अंत हो गया।

--

स्रोत : पी.आर. ब्रास, ऑक्सफोर्ड डी.एन.बी. बायोग्राफी ऑफ चरण सिंह २००९; पी.आर. ब्रास, फेक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टैट : दि कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश (१९६६)। पालियायामेंट ऑफ इंडिया, सेवेन्थ लोक सभा, हू. इज हू १९८० (१९८०)। दि टाइम्स (३० मई १९८७) ए म्हामिया, दि आउटस्टेंडिंग किसान लीडर (२००२) [गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इन्फॉर्मेशन व्यूरो] टी.जे. बायर्स 'चरण सिंह (१९०२-१९८७) : एन एसेसमेंट' जर्नल ऑफ पीजैट स्टडीज, १५/२ (जन १९८८), १२९-८९ पी.आर. ब्रास, 'चौधरी चरण सिंह : एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ', इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, २८/३९ (२५ सित. १९९३), २०८७-९० ए पी.आर. ब्रास पर्सनल नॉलेज (२००८) पी.आर. ब्रास, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन (२००८) हर्ष सिंह लोहित - पर्सनल नॉलेज (२०१५)